गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय
गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की आकस्मिक 32वीं बैठक दिनांक 30.10.2022 को सायं 03:30 बजें ऑनलाईन माध्यम से मा0 कुलपति, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

शिक्षा सोसाइटी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यः

1. प्रो0सुनील कुमार खरे .....सदस्य उपस्थित
   डीन, आर एंड डी एंड
   इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री
   एंजाइम और माइक्रोबियलबायो कैमिस्ट्री लैब,
   रसायनिकी विभाग
   भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली

2. **प्रो0 संतोष कुमार** .....सदस्य उपस्थित
   जीओलाजी डिपार्टमेंट,
   सेंटर ऑफ एडवां सस्टडी, कुमाऊं
   विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

3. **प्रो0 शैलेंद्र सिंह गौरव** .....सदस्य उपस्थित
   डीन, कृषि फैक्ल्टी
   प्रोफेसर एवं पूर्व प्रमुख
   जेनिटक एंड प्लांट ब्रीडिंग डिर्पामेंट
   चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
   मेरठ–240004

विश्वविद्यालय के आचार्य/अधिष्ठातागण/प्रभारी, अधिष्ठातागण

4. **प्रो0 एन.पी. मेलकानियॉ** .....सदस्य उपस्थित
   प्रोफेसर,
   अधिष्ठाता शैक्षिक
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
   अधिष्ठाता स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज
   एण्ड एप्लाईड साइंसेज

5. **प्रो0 श्वेता आनन्द** .....सदस्य उपस्थित
   प्रोफेसर
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ठ स्टडीज एण्ड
   सिविलाईजेशन

6. **डॉ0 इन्दु उप्रेति** .....सदस्य उपस्थित
   एसोशिएट प्रोफेसर
   अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च

7. **डॉ0 नीती राणा** .....सदस्य उपस्थित
   एसोशिएट प्रोफेसर
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट

8. **डॉ0 कीर्ति पाल** .....सदस्य उपस्थित
एसोशिएट प्रोफेसर
प्रभारी, अधिष्ठाता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग

9. **डॉ0 कृष्णकांत द्विवेदी** .....सदस्य उपस्थित
प्रभारी, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस
एण्ड गवर्नेंस

10. **डॉ0 मनमोहन सिंह सिसोदिया** .....सदस्य अनुपस्थित
प्रभारी, छात्र कल्याण

कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यः

11. **प्रो0 वंदना पाण्डेय** .....सदस्य उपस्थित
प्रोफेसर
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड
सोशल साईसेंज

12. **प्रो0संजय कुमार शर्मा** .....सदस्य उपस्थित
प्रोफेसर
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ आई.सी.टी.

सचिव प्रबन्ध बोर्डः–

13. **डॉ0विश्वास त्रिपाठी** .....सचिव उपस्थित
कुलसचिव
गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिशिती सदस्यः

14. **प्रो0 विवेक कुमार** .....सदस्य उपस्थित
प्रोफेसर
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित सदस्यः

15. **श्री विभव मिश्रा** .....सदस्य उपस्थित
विश्वविद्यालय सूचीबद्ध अधिवक्ता

औद्योगिक विकास के प्रतिनिधिः

16. **श्री मानवेन्द्र सिंह** .....सदस्य अनुपस्थित
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0

::कार्यवाही का विवरण::

प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों के स्वागत के साथ विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं आकस्मिक बैठक आरम्भ हुई।

32.30.01 प्रबन्ध बोर्ड की तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 20 सितम्बर,2022 को सम्पन्न हुई तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

32.30.02 प्रबन्ध बोर्ड की तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।

विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 20 सितम्बर,2022 को सम्पन्न हुई तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

32.30.03 प्रबन्ध बोर्ड की इक्कतीसवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 03 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न हुई इक्कतीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

32.30.04 प्रबन्ध बोर्ड की इक्कतीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।

विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 03 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न हुई तीसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

32.30.05	**मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा WRIT - A , No. - 7156 of 2020 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही पर विचार एवं निर्णय।** विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा मा0 कुलपति महोदय के कार्यालय में कार्यरत श्रीमती मीना सिंह, स्टाफ आफिसर टू वी.सी (निलंबित) द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से कूटरचित पी.एच.डी. की डिग्री प्रस्तुत करने के विषयक निलम्बन का संज्ञान लिया गया तथा तद्प्रकरण में जाँच किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नामित जाँच अधिकारी द्वारा प्रेषित की गयी जाँच रिपोर्ट को मा0 सदस्यों को पढ़कर अवगत कराया गया। जाँच रिपोर्ट का सार निम्नानुसार है:– (i) Article – I: Doubtful Integrity- Proved (ii) Article – II: Concealment of material facts- Proved (iii) Article– III: Misleading the University Authority- Proved (iv) Article – IV: Not proved उक्तानुसार प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा जाँच रिपोर्ट का सम्यक परिशीलन किया गया एवं गहन विचार–विमर्श के साथ तथ्यों का संज्ञान लिया गया। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा श्रीमती मीना सिंह, स्टाफ आफिसर टू वी.सी (निलंबित) द्वारा अपने निलम्बन के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या– WRIT - A , No. - 7156 of 2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित संलग्न आदेश दिनांक 21.09.2022 का भी संज्ञान लिया गया। उपर्युक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन तथा श्रीमती मीना सिंह, स्टाफ आफिसर टू वी.सी (निलंबित) द्वारा विश्वविद्यालय के द्वितीय कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.09.2022 के क्रम में प्रेषित उनके प्रतिउत्तर दिनांक 10.10.2022 का भी प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान लिया गया। प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को श्रीमती मीना सिंह द्वारा वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष एजूकेशन विभाग में सहायक आचार्य (Assistant Professor) पद हेतु आवदेन करते समय स्वयं द्वारा हस्तलिखित आवेदन पत्र एवं स्व–सत्यापित पी.एच.डी डिग्री प्रस्तुत की गयी जिसमें उपरोक्त वर्णित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा प्राप्त

कूटरचित डिग्री को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त श्रीमती मीना सिंह के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा स्वयं मूल्यांकन आख्या विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत करते समय उक्त कूटरचित पी.एच.डी डिग्री का उल्लेख किया गया।

तदानुसार प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा विचार किया गया कि श्रीमती मीना सिंह, स्टाफ आफिसर टू वी.सी कुलपति कार्यालय में कार्यरत है तथा कुलपति कार्यालय के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पृकृति के होते है। ऐसी दशा में कुलपति के स्टॉफ आफिसर टू वी.सी. द्वारा स्वयं की सेवाओं में ही कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना एक अत्यंत गम्भीर विषय है। समयानुक्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि भी स्थापित की गयी है यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा–नियुक्ति कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त करता है तो ऐसी नियुक्ति को सेवायोजक द्वारा समाप्त करना ही यथोचित होता है अन्यथा नियुक्ति को बहाल रखना सम्बन्धित कर्मचारी के कूटरचना को वैधानिकता देने के समान हो जाता है। यह तथ्य विश्वविद्यालय के सूचीबद्ध अधिवक्ता, श्री विभव मिश्रा द्वारा (विशेष आमंत्रित) द्वारा अशोक कपिल बनाम सना उल्लाह, (1996) 6एस. सी.सी 392, भारत गणराज्य बनाम एम. भाषकरन (1996) 4एस.सी.सी 416, आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2004) 2 एस.सी.सी 105 एवं रामशरण बनाम आई.जी पुलिस के.रि.पु.ब. एवं अन्य (2006) 2 एस.सी.सी 541के आधार पर उक्त विधि व्यवस्था मा0 सदस्यों के संज्ञान में लायी गयी।

उक्त के दृष्टिगत मा0 प्रबन्ध बोर्ड के समस्त सम्मानित सदस्यों द्वारा यह मतस्थिर किया गया कि कुलपति कार्यालय की महत्ता, संवेदनशीलता, गोपनीयता एवं सूचिता को सुनिश्चित करने हेतु तथा जाँच अधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट के क्रम में श्रीमती मीना सिंह, स्टाफ आफिसर टू वी. सी (निलंबित) की सेवा को विश्वविद्यालय से तत्काल प्रभाव से समाप्त (Remove) किया जाये।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यह भी संज्ञान लिया गया कि प्रबन्ध बोर्ड की एक सम्मानित सदस्या प्रो0 श्वेता आनन्द, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ठ स्टडीज एडं सिविलाईजेशन, श्रीमती मीना सिंह के स्टॉफ आफिसर टू वी.सी. के पद पर पदोन्नती की समिति की सदस्या रही है। अतः उन्हे इस चर्चा में मत देने से विरक्त रखा गया है।

तदानुसार विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा कुलसचिव, गौतम बुद्ध विश्ववद्यिालय को निर्देशित किया गया कि श्रीमती मीना सिंह, स्टाफ

	आफिसर टू वी.सी (निलंबित) की सेवा को बिश्वविद्यालय से तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने सम्बन्धी सलंग्नानुसार आदेश निर्गत करें।

32.30.06 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ0 विश्वास त्रिपाठी)
सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव
गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय

(प्रो0 रविन्द्र कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलपति
गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय

ORDER

On the receipt of the complaint regarding forged and fabricated PhD degree of Smt. Meena Singh (*previously known as Ms. Meena Rani*), the then Staff Officer of the Vice Chancellor- Gautam Buddha University, *hereinafter referred to as the Charged Officer (C.O.),* verification of degree was sent by the Registrar- Gautam Buddha University, *hereinafter referred to as the G.B.U.*, to the University from which the degree was allegedly issued, i.e. Chaudhary Charan Singh University, Meerut, *hereinafter referred to as the CCS University- Meerut,* whereupon vide Conf. Letter No. 4212 dated 18.08.2020 issued jointly by the Vigilance Officer and Controller of Examination, CCS University, Meerut addressed to the Vice Chancellor- GBU, the CCS University, Meerut confirmed that no candidate with the name Meena Rani D/o Sh. Jeet Ram was registered for PhD and that no PhD Degree with even Registration No. was issued by CCS University, Meerut in 2009 in the subject of Education, consequent upon which Smt. Meena Singh was put under suspension vide Order dated 18.08.2020 and departmental disciplinary proceedings were initiated under the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1991 read-with Rule of the University Ordinance.

The charges framed against the C.O. were approved by the disciplinary authority and the chargesheet along-with all relevant documents were supplied to the C.O. The C.O. was given 10 opportunities for oral hearing, pursuant upon the denial of the charges. The oral hearings were conducted on date 08.01.2021, 21.01.2021, 25.01.2021, 10.02.2021, 13.02.2021, 18.02.2021, 27.02.2021, 09.03.2021, 13.03.2021 and 19.03.2021, and the Daily Order-Sheets were drawn.

On the first and second hearing, i.e. on 08.01.2021 and 21.01.2021, the C.O. expressed her inability to appear before the Inquiry Officer, however, on all subsequent dates, the C.O. appeared and was given all opportunities to lay her defence as recorded in the daily order-sheet duly countersigned by the Charged Officer.

The enquiry was conducted under the above-said rules and out of four charges against the C.O., three charges were proved against her. The charges proved against the Charged Officer were (i) Article – I: Doubtful Integrity, Article – II: Concealment of material facts and Article– III: Misleading the University Authority, stood as proved, whereas violation of Rule 9 of the University Ordinance (Article – IV) was not proved.

In the Course of Inquiry, C.O. restricted her defence to the fact that prefixing "Dr." before her name was purely inadvertent and she had no motive in this regard. She categorically stated that after registration for her Ph.D., her parents started calling her "Dr." knowing well that she was not awarded any such PhD Degree, which was later followed by prefixing it with her name. Further, she stated that it continued like that inadvertently. Also, it was submitted by her that she never claimed in her entire service that she is PhD holder and it was an innocent act.

It is noteworthy to observe that in her initial application on 05.07.2010 and 07.07.2010, the C.O. disclosed that she was pursuing her Ph.D. from Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur and in the later correspondence of 2011 the C.O. herself submitted two self-attested

photocopies of Ph.D. degree which was issued to her by CCS University, Meerut, after which the C.O. started prefixing her name with "Dr". The same self-attested exhibited copy of the Ph.D. degree which was submitted by the C.O., was sent for verification.

In another defence taken by the C.O. justifying her conduct, the C.O. stated that she has not derived any benefit from the PhD Degree and that the essential qualification for the appointment on the post of Staff-Officer of the Vice Chancellor is graduate degree with minimum 55% marks, which she was possessing on the date of her appointment. Therefore, per C.O., to consider whether the C.O. was PhD degree holder or not, was irrelevant. Per contra, it is seen that out of Secretarial cadre, the CO got promoted to the post of Staff-Officer of VC from P.S. to VC on consideration of the PhD degree.

The second explanation furnished by the C.O. is admission in itself. The statement of the CO that she has not derived any benefit of the PhD degree itself means that the PhD was furnished by her, but it was of no 'use' to her.

On the complaint of the Shri S.N. Tiwari, the then Officiating Registrar, FIR No.166 dated 12.11.2020, PS Ecotech-I, District Gautam Budh Nagar u/s 420, 467, 468, 471 of IPC was registered and against the C.O. after grant of Application No.18 of 2020 u/s 156(3) Cr.P.C. vide order dated 06.11.2020. Challenging the FIR, Smt. Meena Singh filed Crl. Misc Writ Petition No. 16275/2020 before the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, which was dismissed as not-pressed.

On the perusal of the entire records- the report of the Enquiry Officer, defence laid down by the Charged Officer, the reply to the second show cause notice, the explanations furnished by the Charged Officer are not satisfactory. The self-attested copies of the PhD Degree was admittedly furnished by the CO to her Employer which was forged and fabricated.

Towards this, the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India is clear. In Union of India vs. M. Bhaskaran (1996) 4 SCC 416, Supreme Court held that such orders of removal (after detection of fraud) would amount to recalling of fraudulently obtained erroneous appointment orders. Supreme Court further observed that even independently of rule 3(1)(i) and (iii) of the rules, such fraudulent appointment orders could be legitimately treated as avoidable at the option of employer and could be recalled by the employer and in such cases, the factum of employees having continued in service for a number of years on the basis of such fraudulently obtained employment orders, cannot create any equity in their favour or any estoppel against the employer. Supreme Court further observed that, no Court should be a party to the perpetuation of the fraudulent practice. By such fraud or intended fraud on the employer or on the appointing authority the aggrieved are all those who had similar or even better qualifications than the appointee or appointees, but who could not apply for the post because of fraud played by those who obtained appointment by fraud. It amounts to fraud on public. If by doing fraud an appointment is obtained, such fraudulent practice cannot be permitted to be continued by a court of law in directing reinstatement of respondent workman with all consequential benefits.

In Ashok Kapil v. Sana Ullah (Dead and Ors) (1996) 6 SCC 392, the maxim "Nullus Commodum Capere protest de injuria sua propria" (No one can take advantage of his own wrongs) is one of the salient tenets of equity. The respondent cannot secure the assistance of a court of law for enjoying the fruits of his own wrong. Further, in R.Vishwanatha Pillai v. State of Kerala & Ors. 2004 (2) SCC 105, pertained to termination of services of the petitioner on the ground that he got appointment on the basis of a false caste certificate. Supreme Court observed that the right to salary or pension after retirement flows from a valid and legal appointment. The consequential right of pension and monetary benefits can be given only if the appointment was valid and legal. Such benefits cannot be given in a case where the appointment was found to have been obtained fraudulently and rested on false caste certificate. A person who entered the service by producing a false caste certificate and obtained appointment to the post meant for Scheduled Caste, thus depriving the genuine Scheduled Caste of appointment to that post, does not deserve any sympathy or indulgence of the Court. A person who seeks equity must come with clean hands. He, who comes to the Court with false claims, cannot plead equity nor the Court would be justified to exercise equity jurisdiction in his favour. No sympathy and equitable consideration can come to his rescue.

In Ram Saran v I.G. of Police, CRPF and Ors, 2006(2) SCC 541 Supreme Court held that no leniency can be shown to a person who has obtained appointment on the basis of forged documents, otherwise it shall amount to giving premium to a person who committed forgery.

Considering the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, the degree verification report of the CC University- Meerut, the admission of the C.O., it is appropriate that major penalty, i.e. removal from the service which does not disqualify from future employment should be given to the CO.

Therefore, it is ordered that the Smt. Meena Singh (Staff Officer to VC (Under Suspension)) be removed from the service with immediate effect. However, the Smt. Meena Singh will not be disentitled from seeking any future employment.

The Accounts Department is directed to do the needful under the Rules laid down under the Act/ Statute and Ordinance of the University and in the light of the Financial Handbook Volume-II, Part-II, Chapter-VIII.

Smt. Meena Singh may file an appeal against this order before the Appellate Authority within statutory period, if so desire.

The Registrar is directed to communicate this order to Smt. Meena Singh with immediate effect.

Dated: 30.10.2022

THE BOARD OF MANAGEMENT
GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY